the Delhi Municipal Corporation Act to remove obstructions.

जम्मू और कश्मीर से लोगों का घर छोड़कर चले जाना

4477. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर से घर छोड़कर आए हुये लोगों ने वहां अपने घरों में वापस जाने के लिये उनकी क्या शर्त हैं और इस शर्त को पूरा करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई आ रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) यह उम्मीद है कि घाटी में स्थिति में सुधार आने पर कश्मीरी प्रवासी अपने घरों को वापस चले जाएंगे । राज्य में आतंकवाद को रोकने और सामान्य हालात बहाल करने के लिए संगठित कार्रवाई की जा रही है ।

Effects of Indiscriminate use of TADA on Tourism

4478. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that indiscriminate use of TADA by some State Governments is sending wrong signals to foreign countries, as a result of which foreign tourism campaign is being adversely effected; and

(b) if so, what steps Government are taking to prevent adverse effect on tourism thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) In order to avoid any misuse of TADA, the State Governments were requested to issue suitable guidelines regarding registration and investigation of cases under the Act on the basis of the draft guidelines sent to them by the Central Government. It has been re-emphasized that the Act should be used only against the terrorists or their collaborators and should not be invoked against journalists, trade union leaders political dissenters or against such cases wherein the normal laws are adequate to deal with the situation.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

4479. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि अत्याचारों की सर्वाधिक घटनाएं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होती हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मामले पंजीकृत किये गये और कितने लोगों को सजा दी गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) वर्ष 1989; 1990 तथा 1991 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के मामलों की संख्या के आंकड़े, राज्यवार/संघशासित क्षेत्रवार अनुलग्न में दिए गए हैं । [देखिए परिशिष्ट 164, अनुपत्र संख्या 76]

केन्द्रीय सरकारी ऐजेंसियों द्वारा उन मामलों की संख्या के बारे में आंकड़ों का